



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ 1935 (श0)
(सं0 पटना 468) पटना, मंगलवार, 18 जून 2013

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय,
गृह विभाग

अधिसूचनाएं
29 मई 2013

सं0 2758—भारत संविधान के अनुच्छेद-39 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अपराध से पीड़ितों के कल्याण हेतु प्रावधान करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।—(i) यह नियमावली “बिहार अपराध पीड़ित कल्याण न्यास नियमावली, 2013” कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत के प्रभाव से लागू होगा।

2. परिभाषाएँ।— इस नियमावली में जब तक कोई बात संदर्भ में विरुद्ध न हो:-

(i) “सरकार” से अभिप्रेत है “राज्य सरकार, बिहार;

(ii) “अपराध पीड़ित कल्याण न्यास” से अभिप्रेत है, अपराध पीड़ितों के लाभ के प्रयोजनार्थ न्यास;

(iii) “व्यवस्थापक-अध्यक्ष” से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव गृह विभाग;

(iv) “व्यवस्थापक सचिव” से अभिप्रेत है निदेशक प्रोवेशन सेवा;

(v) “न्यासी” कोषाध्यक्ष” से अभिप्रेत है बंदी कल्याण पदाधिकारी;

(vi) “न्यासी” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो विश्वास प्राप्त करता है;

(vii) “न्यासी” सदस्य से अभिप्रेत है पदेन महानिरीक्षक, आन्तरिक वित्तीय सलाहकार गृह विभाग, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि जो (संयुक्त सचिव से अन्यून) हो, केन्द्रीय कारा अधीक्षक (वार्षिक रोस्टर वार पदस्थापित) एवं महानिरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित वरीयतम प्रोवेशन पदाधिकारी;

(viii) “न्यास-भंग” से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा न्यासी को उस रूप में अधिरोपित किसी कर्तव्य का भंग;

(ix) न्यास की आस्तियां से अभिप्रेत है “न्यास सम्पत्ति” धन अथवा अन्य सामग्रियां;

(x) “रजिस्ट्रीकृत” से अभिप्रेत है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (अधि0 संख्या 16, 1908) के अधीन रजिस्ट्रीकृत;

(xi) “बचत बैंक खाता” से अभिप्रेत है किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बचत खाता।

3. अपराध पीड़ित कल्याण न्यास का प्रयोजन।—सश्रम कारावास के सिद्धदोष बंदियों को पारिश्रमिक देने का प्रावधान है। सिद्धदोष बंदियों की मजदूरी के कतिपय भाग की कटौती की जाती है और उसे न्यास के बचत खाता में अपराध से पीड़ित परिवार के सदस्यों लाभार्थ जमा किया जाता है। ऐसी जमा राशि का वितरण अपराध से पीड़ितों के बीच वितरण किया जाना ही अपराध पीड़ित कल्याण न्यास का मुख्य उद्देश्य एवं हेतुक है।

4. न्यास की सम्पत्ति।— राज्य के विभिन्न काराओं में संसीमित सजावार बंदियों के पारिश्रमिक में से अपराध से पीड़ितों के लाभार्थ की गयी कटौती की राशि न्यास की सम्पत्ति होगी। ऐसी राशि राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाता जो प्रधान सचिव/सचिव-सह-व्यवस्थापक न्यास एवं बंदी कल्याण पदाधिकारी-सह-न्यास कोषाध्यक्ष के संयुक्त पदनाम से होगी, में जमा की जायेगी। जमा राशि की निकासी, व्यवस्थापक अध्यक्ष एवं न्यास कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से, की जाएगी।

5. अपराध पीड़ित कल्याण न्यास की कार्य प्रणाली।—

- (1) अपराध पीड़ित कल्याण न्यास की बैठक सामान्यतः वर्ष में दो बार होगी। किन्तु आवश्यक होने की दशा में अतिरिक्त बैठक भी बुलाई जा सकेगी।
- (2) बैठक के लिए न्यूनतम 7 दिनों की नोटिस होगी, किन्तु विशेष परिस्थिति में कम समय के नोटिस पर भी बैठक बुलाई जा सकेगी।
- (3) अपराध पीड़ित कल्याण न्यास की बैठक हेतु गणपूर्ति पाँच सदस्यों से होगी, जिसमें अध्यक्ष एवं सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- (4) जिला स्तर पर गठित समिति से, अपराध पीड़ितों के कल्याण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपराध पीड़ित कल्याण-न्यास बैठक में प्रस्ताव पर विचार करेगा और सम्यक् विचारण के पश्चात लाभार्थियों को लाभ देने हेतु विनिश्चय करेगा।
- (5) अपराध से पीड़ित परिवार को दी जाने वाली राशि की सीमा संबंधित बंदी से की कटौती किये गए पारिश्रमिक के अंश की सीमा की भीतर होगी।
- (6) लाभार्थियों को चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

6. जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा प्रस्ताव अपराध पीड़ित कल्याण न्यास को भेजा जाना।—

- (1) प्रत्येक जिला में एक “जिला स्तरीय अपराध पीड़ित कल्याण समिति” का गठन किया जायेगा, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे एवं संबंधित जिला के केन्द्रीय/मंडल कारा के अधीक्षक सदस्य सचिव होंगे, एवं जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा सभी मनोनीत प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी या वरीय प्रोवेशन पदाधिकारी, इसके सदस्य होंगे।
- (2) जिला स्तरीय “अपराध पीड़ित कल्याण न्यास” की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार होगी।
- (3) कारा अधीक्षक-सह-सचिव सभी प्रस्ताव जिन्हें जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाना है, के संबंध में बैठक के पूर्व प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी/वरीय प्रोवेशन पदाधिकारी के माध्यम से अपराध से पीड़ित परिवार के सदस्यों के चिन्हितकरण की कार्यवाई करा लेंगे।
- (4) इस प्रयोजनार्थ सचिव प्रत्येक दोषसिद्ध बंदी की एक व्यक्तिगत संचिका संधारित करेंगे तथा प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी को अपराध पीड़ित की पहचान के लिए माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी।
- (5) प्रोवेशन पदाधिकारी न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपराध पीड़ित की पहचान करेंगे तथा जब कभी प्रतिवेदन मांगा जाय एक माह के भीतर प्रतिवेदन देंगे। प्रोवेशन पदाधिकारी वर्तमान पता के साथ पीड़ितों के बारे में प्रतिवेदन देंगे।
- (6) प्रोवेशन पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय कल्याण समिति के समक्ष सचिव द्वारा रखा जायेगा और उक्त समिति उत्तराधिकार अधिनियम के आलोक में अपराध पीड़ितों को दिये जाने वाले लाभ की राशि विनिश्चित करेगी।
- (7) समिति की बैठक की कोरम की पूर्ति मात्र चार सदस्यों से होगी, जिसमें अध्यक्ष और सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बराबरी मत की स्थिति में, अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देगा।

7. जब विभिन्न काराओं से प्रस्ताव प्राप्त हो जाय को व्यवस्थापक सचिव-सह-निदेशक प्रोवेशन चर्या व्यवस्थापक अध्यक्ष को जानकारी देंगे।

8. न्यास के लाभार्थी बंदियों के अपराध पीड़ित होंगे।

9. अपराध पीड़ित कल्याण न्यास के कोई भी न्यासी न्यास संपत्ति का उपयोग किसी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

10. न्यासी न्यास सम्पत्ति से परिचित होंगे।

11. कोई न्यासी न्यास सम्पत्ति से वैसे ही सावधानी से निपटने के लिए आवद्ध होंगे जैसा मामूली प्रज्ञा वाला व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति से निपटता यदि वह उसकी अपनी सम्पत्ति होती।

12. न्यासी न्यास सम्पत्ति पर अपने या किसी अन्य के लिए ऐसा कोई भी हक, जो हिताधिकारी के हित के प्रतिकूल हो, न तो खड़ा करेगा और न ऐसा कोई हक जोड़ेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन)।

The 29th May 2013

No. 2758—In Exercise of the powers under Article 39 of the constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules to provide provision for welfare of the victims of offence.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called "**BIHAR VICTIMS OF THE OFFENCE WELFARE TRUST RULES, 2013**"

(2) It will extend to the whole of Bihar.

(3) it shall come into force with immediate effect.

2. Interpretation-clause.—

- (i) Government means State Government of Bihar,
- (ii) '**Victims of the Offence Welfare Trust**' means – Trust for the purpose of benefit of victims of the offence.
- (iii) '**Settlement Chairman**' means Principal Secretary/Secretary, Home Department.
- (iv) '**Settlement Secretary**' means Director, Probation Services.
- (v) '**Trustee Treasurer**' means Prison Welfare officer.
- (vi) '**Trustee**' means The person who accepts the confidence;
- (vii) '**Trustee member**' means Inspector General of Prisons; Internal Financial Advisor, Home Department; Representative of Social Welfare Department (not below the rank of the Joint Secretary); Central Jail Superintendent (yearly roster wise) and the senior most Probation Officer nominated by the I.G. Prison posted at Jail Inspectorate, Bihar, Patna ex- offico
- (viii) '**Breach of Trust**' means A breach of any duty imposed on a trustee as such by any law for the time being in force is called a breach of trust.
- (ix) '**Assets of a Trust**' means trust property, trust money or other material;
- (x) '**Registered**' means - registered under the Registration Act, 1908 (Act No 16 of 1908).
- (xi) '**Saving Bank Account**' means Saving Account of any Nationalised Bank.

3. Aims and object of the Victims of the offence welfare trust.—There is a provision to give the wages to the convicted prisoner for rigorous imprisonment. Certain portion of the wages of the convicted prisoners shall be deducted and it is deposited in the Bank account of the trust for the benefit of the victims of the offence. To distribute such deposited amount among the victims of the offence, is the main aims and object of the **victims of the offence welfare trust.**

4. Property of the trust.—The amount deducted from wages of the convicted prisoners of different jails of the State, shall be the property of the trust. Such amount shall be deposited in the Saving Account of the Nationalised bank, which will be in the joint name of the Principal Secretary/Secretary, Home Department-cum-Chairman Settler and Prisons Welfare Officer-cum-Trustee Treasurer. Deposited amount shall be withdrawn by joint signature of the settlement Chairman Settler and Trustee Treasurer.

5. Working System of the victims of the offence welfare trust.—(1) The meeting of the victims of the offence welfare trust shall generally be held twice in a year but in case of need an additional meeting also may be called up.

- (2) 7 days prior notice will be necessary for the meeting of the victims of the offence welfare trust. But in special circumstances meeting may be called up at short notice.
- (3) The coram for the meeting of the victims of the offence welfare trust will be present with the five members in which the presence of the Chairman and the Secretary of the trust will be compulsory.
- (4) After receiving the proposal from the committee constituted at the district level for the welfare of the victims of the offence, victims of the offence welfare trust shall consider the proposal in its meeting and after due consideration shall take decision to give the benefit to the beneficiary.
- (5) The Limit of the the amount to be paid to victims of the offences shall be within the limit to the portion of the wages deducted from the concerned convicted prisoners.
- (6) Payment to the beneficiary shall be made through account payee cheque.

6. Proposal to the victims of the offence welfare trust from committee constituted at the district level.—

- (1) District level victims of the offence welfare committee shall be in each district chairman of which will be District Magistrate and Central/District Jail Superintendent of the concerned district shall be the Member secretary of the district level committee and the District welfare Officer, District Account Officer, District Prosecution Officer and The Principal Probation Officer/Senior Most Probation Officer of concern district all nominated by District Magistrates, shall be members of committee.
- (2) The meeting of the Districts level Committee of the **Victims of the offence welfare Trust** shall be held at least once in every quarter.
- (3) Secretary-cum-Jail Superintendent shall get the victims of the offence identified shall get through the Principal Probation Officer/Senior Probation Officer, before the meeting of the committee, all proposals which has to be put up before the committee in its meeting.
- (4) For this purpose, Secretary shall maintain the individual file of the each convicted prisoner and for identification of the victims of the offence, the principal probation officers shall be provided with a copy of Judgment of the Hon'ble Court.
- (5) The probation officer shall identify the victims of the offence in the light of the judgment of the court and submit the report whenever asked for, within a month. The probation officers shall also report about the where about of victims with their present address.
- (6) The proposal which is received from the probation officer shall be put up before the District level victims welfare committee by the Secretary and the aforesaid committee shall decide the beneficial amount to be given to the victims of the offence in light of the Succession Act.
- (7) The quorum of the meeting of the committee shall be present with of four members in which the presence of Chairman and Secretary is compulsory. In case of equal votes, will cast the chairman his casting vote final.

7. The Settler Secretary-cum-Director Probation shall bring to the knowledge of the Chairman Settler-cum-Principal Secretary/Secretary, Home Department, when the proposal is received from the different jails.

8. Beneficiary of the trust shall be the victims of the offence of the Prisoners.
9. The trustee of **victims of the offence welfare trust** shall not be authorised to utilise the trust property for any personal benefit.
10. The trustee shall be acquainted with the property of the trust.
11. A trustee is bound to deal with the trust property as carefully as a man of ordinary prudence would deal with such property.
12. The trustee must not for himself or another set up any aid or any title to the trust property adverse to the interest of the beneficiary.

**By order of the Governor of Bihar,
SATYENDRA NATH SRIVASTAVA,
Joint Secretary-Cum-Director (Admin).**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 468-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>